खाकी लैंगिक दादागीरी का चलन और लव जिहाद की राजनीति

विकास नारायण राय

किसी भी कानून-व्यवस्था के लिए दुस्स्वप्न जैसा ही रहा होगा जब एक कालेज छात्रा अपने सहपाठी द्वारा लैंगिक जुनून में मौत के घाट उतार दी जाए और ऊपर से पुलिस की जांच पर लव जिहाद की नफरती राजनीति को भी हावी होने दिया जाए। समाज का एक तबका त्वरित न्याय के नाम पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा पुलिस से भी 'एनकाउंटर' की मांग पर उतर आया है, लेकिन स्त्री-द्वेष के विस्फोट के इस अवसर पर लेखक-जर्नलिस्ट प्रियंका दुबे की आँख खोल देने वाली यह फेसबुक टिप्पणी पढ़ी जानी चाहिए :

''निकिता तोमर हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज दिल दहला देने वाला है। पितृसत्ता के ठेकेदारों को किसी ने कभी सिखाया नहीं कि कन्सेंट किसका नाम है। जिनको फ़ेमिनिज़्म की ज़रूरत महसूस नहीं होती या यह लगता है कि औरतें अपने घावों के दुखने पर बेवजह ज़्यादा शोर मचा रही हैं उनके पास अगर सब्र हो तो वह क्लिप देखें। इस देश में परीक्षा हाल से निकल घर जा खाना खाने की बजाय सीने पर गोली खा रही हैं लड़कियाँ- सिर्फ़ लड़की होने की वजह से। लेकिन चुल्लू भर पानी आपको मिलेगा नहीं डूब जाने के लिए. क्योंकि इतनी आसान भी नहीं है मुक्ति - जो घाव हम लेते आ रहे हैं अपने सीनों पर, वह सिर्फ़ हमारे शरीर के घाव नहीं हैं...बल्कि इस देश की आत्मा पर लगे घाव हैं।''

बल्लभगढ़, फ़रीदाबाद में सोमवार को सरेआम दिन-दहाड़े एक शोहदे द्वारा कालेज गेट पर छात्रा के अपहरण की कोशिश के बाद उसकी गोली मार कर हत्या जैसे निरंकुश अपराध में समाज और प्रशासन के लिए भी सबक हैं। दोनों बारहवीं तक के स्कूल में साथ थे और 2018 में भी इसी लड़की को लेकर इसी लड़के पर अपहरण का केस दर्ज हुआ था जो बाद में दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से बंद कर दिया गया था। सारे प्रकरण में हिंदू लड़की-मुस्लिम लड़के वाला सामाजिक तनाव का पक्ष ही नहीं, लड़के द्वारा लड़की पर अपनी मर्ज़ी लादने का लैंगिक आयाम भी शामिल रहा है। हत्या के बाद राज्य के भाजपायी गृहमंत्री अनिल विज ने भी लड़की पर तथाकथित 'धर्म परिवर्तन' के दबाव का सवाल हाइलाइट करना शुरू कर दिया है। 2018 में उन्हीं की सरकार और पुलिस के लिए यह एक सामान्य आपराधिक विचलन था जिसमें समझौता कराया जा सकता था।

स्वभाविक था कि इस पशुवत अपराध से स्तब्ध समाज में एकबारगी घोर उत्तेजना की लहर दिखी और स्थानीय कानून-व्यवस्था को भी बेहद तनाव भरे क्षणों से गुजरना पड़ा। हालाँकि, पोस्ट-मार्टम के बाद, संभावित शांति भंग की आशंका में, लड़की के शव को परिजनों को सौंपने में देरी होने से कटुता रही लेकिन पुलिस को श्रेय देना होगा कि उन्होंने तेजी से कार्यवाही करते हुए राजनीतिक परिवार से जुड़े मुख्य आरोपी को चंद घंटों में ही गिरफ़्तार कर लिया था। न तो राजनीतिक प्रभाव रखने वाले आरोपी के परिवार और न ही किसी अन्य दिशा से उसकी वकालत की गयी। तो भी, हिंदुत्व की ज़हरीली विभाजक राजनीति करने वाले तत्वों ने वातावरण को और दूषित करते हुए 'लव जिहाद' का साम्प्रदायिक ढोल पीटने में कसर नहीं छोड़ी।

राजनीति करने वाले तत्वों ने साम्प्रदायिक ढोल पीटने में कसर नहीं छोड़ी

समझना होगा कि व्यापक समाज की सोच और व्यवहार में भी शासन का ही प्रतिरूप छिपा होता है। समाज को मानवीय और उदार बनाना है तो शासन तंत्र को मानवीय और उदार बनाने की ज़रूरत है। इसी समीकरण का दूसरा पहलू हुआ कि शासन को सशक्त करने के लिए समाज को भी सशक्त करना होगा। इस लिहाज़ से, कानून-व्यवस्था में विश्वास पैदा करने के लिए, शायद सबसे अधिक पुलिसकर्मी को स्वयं को ही बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। वह सार्वजनिक रूप से शासन के पहिये को खींचने वाला प्रशासन का सबसे प्रकट एजेंट होता है।

फिलहाल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिणी पड़ोस में हुए इस घृणित कांड की मीडिया में व्यापक गूंज तो है लेकिन मुख्यत: टीआरपी संचालित। जबकि दिल्ली के उत्तरी पड़ोस, गोहाना, सोनीपत में एक नाबालिग दलित लड़की के पुलिस हिरासत में सामूहिक बलात्कार पर यही मीडिया महीनों से ख़ामोश है क्योंकि वहाँ 3 नवंबर को विधानसभा की बरोदा सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहां के आरोपी समाज के जिस प्रभावी तबके से आते हैं, उसके वोट हर राजनीतिक दल को चाहिए और हर किस्म की मीडिया को भी इस या उस राजनीतिक दल के व्यवसायिक आश्रय की दरकार होती ही है।

डर है कि बल्लभगढ़ और गोहाना जैसे गहरे लगे लैंगिक घाव युवा पीढ़ियों में अन्दर ही अन्दर नासूर बनकर न रिसते रहें।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

राष्ट्रीय नासमझी और बेवकूफ हरकतों की वजह से घिर गए हैं मुसलमान

यूसुफ किरमानी

पियू रिसर्च (Phew Research Center) की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक़ पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी 1 अरब 80 करोड़ है। आबादी के मामले में ईसाइयों के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। इन दोनों समुदायों के बीच सदियों से चली आ रही रस्साकशी के अब नये आयाम सामने आ रहे हैं।

दुनियाभर में अंतरराष्ट्रीय प्रचार तंत्र से मुसलमान घिर गया है। कहीं वो अपनी नासमझी और बेवक़ूफ़ हरकतों से घिरे हैं तो कहीं बाक़ायदा साज़िश करके उन्हें घेरा गया है।

सामाजिक समानता, भाईचारे का संदेश देने वाले मज़हब इस्लाम को अचानक इस रूप में पेश किया जा रहा है कि दुनिया के हर देश में मौजूद हर मुसलमान आतंकवादी है। वह धार्मिक उन्मादी है। यह बात उन देशों में भी की जा रही है जहाँ मौजूदा दौर में मुसलमानों के कई धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए। कई शहरों से उन्हें पलायन करना पड़ा। कई शहरों में एक-एक हफ़्ते तक वो दंगे का शिकार होते रहे। असंख्य लोग मार दिए गए और उनका सबकुछ लूट लिया गया। कुछ मामलों में तो उल्टा आरोपी तक बना दिए गए।

ये हालात हमें भारत में 1984 के सिख विरोध की याद दिलाता है। तब सारे सिख आतंकवादी और खालिस्तानी बताये जाते थे और दंगों में उनका सबकुछ लूट लिया गया। लोगों को याद होगा कि सिखों ने अपने ऊपर हुए ज़ुल्मों के लिए मुसलमानों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया था।

इस समय मुस्लिम विरोध का सबसे बड़ा अखाड़ा फ्रांस बना हुआ है।

फ्रांस में पिछले दिनों एक टीचर की उस वक्त बेरहमी से एक मुस्लिम लड़के ने हत्या कर दी थी जब उसने अपनी क्लास में पैग़म्बर का मजाक उड़ाया था। पुलिस ने उस मुस्लिम लड़के को पकड़ा और गोली मार दी। राष्ट्रपति मैक्रां ने इस घटना के लिए पूरे इस्लाम धर्म को ज़िम्मेदार ठहराया और इसे इस्लामिक आतंकवाद बताया।

इस घटनाक्रम के बाद पैरिस के आइफल टावर परिसर में दो मुस्लिम महिलाओं की हत्या कर दी गई। लेकिन मैक्रां ने इसके लिए न तो किसी धर्म को जिम्मेदार ठहराया और न ही घटना की निन्दा की। इसके बाद फ्रांस में फिर एक हत्या हुई और आरोपी मुस्लिम ही है।

जिस दिन मुसलमान नफ़रत को नियंत्रित करने वाले सौदागरों को पहचान लेगा तो नफरती चिंटुओं की दुकान बंद हो जाएगी

फ्रांस के तमाम नागरिक संगठन और विपक्षी राजनीतिक दल मैक्रां के बयान और व्यवहार पर नाराज़ हैं। तुर्की ने फ्रांस के सामानों के बहिष्कार की अपील कर दी है।

फ्रांस की कंपनियों में खलबली मच गई है क्योंकि उनके महँगे उत्पाद सबसे ज्यादा सऊदी अरब में बिकते हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में इस्राइल से दोस्ती की है।...सऊदी अरब के मुसलमानों में सऊदी अरब की राजशाही यानी आल-ए-सऊद ख़ानदान के प्रति ग़ुस्सा बढ़ रहा है। वहाँ तुर्की और ईरान की अपील का ज्यादा असर हो रहा है।

नफ़रत फैलाने वाला प्रचार तंत्र सबसे पहले मुसलमानों को बताता है कि देखो तुम्हारे पैग़म्बर पर कॉर्टून बनाया गया है। किसी न किसी मुसलमान को इसमें पैग़म्बर की बेइज़्ज़ती नज़र आती है। पैग़म्बर पर कूड़ा फेंकने वाली महिला को खुद पैग़म्बर माफ़ कर चुके हैं लेकिन उनकी सीरत पर चलने वाला मुसलमान कॉर्टून बनाने वाले को माफ़ करने को तैयार नहीं है। ऐसे बेवक़ूफ़ मुसलमानों को यह भी नहीं मालूम कि जिस नफ़रत फैलाने वाले प्रचार तंत्र ने उसे यह जानकारी दी है, उसे नियंत्रित कौन कर रहा है और उसका इरादा क्या है? जिस दिन मुसलमान या कोई भी समुदाय नफ़रत को नियंत्रित करने वाले सौदागरों को पहचान लेगा और उनके इरादे भाँप लेगा तो नफरती चिंटुओं की दुकान बंद हो जाएगी।

तो असली मुद्दा है नफ़रत के सौदागर कौन हैं? उनके छिपे चेहरों के पीछे कौन हैं। फ्रांस में भारत की तरह आग नहीं फैली है। लेकिन मात्र फ्रांस की घटनाओं को अंतरराष्ट्रीय बना दिया गया। जबकि भारत में सारे साम्प्रदायिक सौहार्द को ताक पर रखकर लिंचिंग की अनगिनत घटनाएँ हुईं।

इंडिया स्पेंड की 2017 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक़ 2014 में मोदी की सरकार आने के बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की 93 फीसदी घटनाएँ हुई हैं। जून 2017 तक भाजपा शासित राज्यों में सरकारी आँकड़ों के मुताबिक़ लिंचिंग के 63 मामले हो चुके थे। जिसमें 32 मामले गोरक्षक दलों के हमले से जुड़े हैं। खुद यूएन और अमेरिकी सीनेट की रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को ख़तरे में बताते हुए चिन्ता जताई गई थी।

भारत में जी न्यूज़, इंडिया टीवी, आजतक, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ बाक़ायदा समुदाय विशेष के खिलाफ नफ़रत का अभियान चला रहे हैं। हाथरस, बुलंदशहर में इन चैनलों को लव जिहाद नहीं दिखता क्योंकि आरोपी मुसलमान नहीं थे लेकिन बल्लभगढ़ में अगर आरोपी मुसलमान है तो उसे फ़ौरन लव जिहाद बता कर नफ़रत का कारोबार चलाया जाता है। लेकिन यह समझ से बाहर है कि भारत में 35 करोड़ मुसलमान और सेकुलर और तटस्थ हिन्दू ऐसी मीडिया को फलने फूलने में क्यों मदद कर रहे हैं जो नफ़रत के कारोबार में जुटे हैं। यही हाल फ्रांस के मुसलमानों का भी है।

मुसलमानों का असली दुश्मन उसके घर में रखा नफ़रत फैलाने वाला टीवी, मोबाइल पर चलने वाली सोशल मीडिया ऐप है। मुसलमान का दुश्मन उसका पड़ोसी या किसी देश के बहुसंख्यक लोग नहीं हैं बल्कि फ़ेसबुक, वाट्सऐप, इंस्टाग्राम से नफरत का ज्ञान बघारने वाले लोग हैं।

(वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक)

बिहार में तेजस्वी यादव की आमद के संकेत

जनचौक ब्यूरो

अभी तक के रुझानों से स्पष्ट है कि भाजपा-जेडीयू गठबंधन बिहार चुनाव हारने जा रहा है चाहे बिके हुए ओपिनियन पोल कुछ भी कहें!

पहले चरण की वोटिंग में कई जगहों पर बम्पर वोटिंग हुयी है। मतदाता भरा बैठा है लॉक डाउन में किसी राज्य के गरीब तबके को नुकसान हुआ है तो उसमे बिहार पहले नम्बर पर है, मतदाता लॉक डाउन की तकलीफों को इतनी जल्दी भूला नही हैं, कोविड-19 महामारी के दौर में बिहार के प्रवासी मजदूरों के प्रबंधन में नीतीश सरकार के तरीकों को लेकर जनता में भारी रोष है। लोजपा का भी पूरे राज्य में जदयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार खड़े करना जो शुरुआत में मास्टर स्ट्रोक लग रहा था वह डिजास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। इसका अल्टीमेटली नुकसान भाजपा को ही उठाना पड़ेगा, लोजपा विधानसभा में कोई बड़ी ताकत नही थी पिछले चुनाव में उसे 2 सीट ही मिली थीं।

कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि पिछले विधान सभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 24.4 प्रतिशत था, जबकि राजद को 18.4 प्रतिशत वोट मिले। लेकिन हमें ये देखना होगा कि भाजपा के ज्यादा वोट शेयर होने के पीछे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना भी एक बड़ा कारण था। भाजपा ने 157 सीटों पर, जबकि राजद ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब स्थिति उल्टी है, दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता यह नही भूली है कि किस तरह से षणयंत्रपूर्वक नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाकर बीजेपी ने सत्ता हथियाई और राजद को दूध में गिरी हुई मख्खी की तरह निकाल फेका।

कहते हैं कि बिहार चुनाव जातीय गोलबंदी के आसपास लड़ा जाता है लेकिन लगता है इस बार केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार के प्रति गुस्सा जातीय गोलबंदी के समीकरण से कहीं ज्यादा प्रभावशाली सिद्ध होने जा रहा है। बिहार चुनाव दरअसल कोरोना महामारी से निपटने में मोदी सरकार का लिटमस टेस्ट है और यकीन मानिए ये अगर बिहार चुनाव हारेंगे तो इसका असर बंगाल चुनाव पर तो पड़ेगा ही साथ ही 2024 तक इनकी अपनी जीती हुई सारी स्टेट यह हार सकते हैं।